घर गुजरात का, बादशाहत आरसीबी की

आइपीएल 2026 के फाइनल में आरसीबी ने गुजरात टाइटंस को पांच विकेट से हराकर जीता दूसरा खिताब

जागरण न्यूज नेटवर्क, नई दिल्ली

चैंपियन बनने के लिए निरंतरता, साहस और दबाव के क्षणों में खुद को साबित करने का माद्दा चाहिए होता है। रायल चैलेंजर्स बेंगलुरु (आरसीबी) ने एक बार फिर यही साबित कर दिखाया। अहमदाबाद के नरेन्द्र मोदी स्टेडियम में आरसीबी ने गुजरात टाइटंस को पांच विकेट से हराकर लगातार दूसरी आइपीएल ट्राफी अपने नाम की। गुजरात ने आरसीबी के सामने 156 रन का लक्ष्य रखा था, जिसे आरसीबी ने विराट कोहली (75*) के अर्धशतक के दम पर 18 ओवर में ही हासिल कर लिया। भले ही अहमदाबाद का नरेन्द्र मोदी स्टेडियम गुजरात टाइटंस का घरेलू मैदान हो, लेकिन आरसीबी के लिए लगातार दूसरे साल लकी साबित हुआ। पिछले साल भी इसी मैदान पर आरसीबी ने पंजाब किंग्स को हराकर 18 साल बाद अपनी पहली आइपीएल ट्राफी जीती थी।

विजेताओं पर हुई धनवर्षा

आरसीबी	20 करोड़ रुपये
गुजरात टाइटंस	13 करोड़ रुपये
राजस्थान रायल्स	7 करोड़ रुपये
सनराइजर्स हैदराबाद	6.5 करोड़ रुपये

अहमदाबाद स्थित नरेन्द्र मोदी स्टेडियम में रविवार को आइपीएल 2026 के फाइनल में गुजरात टाइटंस के विरुद्ध जीत दर्ज करने के बाद बल्ला-हेलमेट उठाए विराट कोहली और प्रसन्न मुद्रा में रायल चैलेंजर्स बेंगलुरु के खिलाड़ी। रायटर >>

चैंपियन की तरह खेली टीम : लीग चरण में शीर्ष स्थान हासिल करने से लेकर क्वालीफायर-1 और फिर फाइनल में गुजरात टाइटंस को परास्त करने तक आरसीबी ने हर मोर्चे पर चैंपियंस टीम की तरह क्रिकेट खेला। कप्तान रजत पाटीदार के नेतृत्व में यह टीम कभी दबाव में बिखरी नहीं और हर चुनौती का जवाब मैदान पर दिया। इसी का परिणाम है कि आरसीबी अब मुंबई इंडियंस (2019, 2020) और चेन्नई सुपरकिंग्स (2010, 2011) के बाद लगातार दो आइपीएल ट्राफी जीतने वाली तीसरी टीम बन गई है। यह जीत रजत पाटीदार को भी आइपीएल इतिहास के सबसे सफल कप्तानों की विशिष्ट सूची में शामिल कर गई। अब वह महेंद्र सिंह धौनी, रोहित शर्मा और गौतम गंभीर के बाद दो आइपीएल ट्राफी जीतने वाले कप्तान बन गए हैं।

आंकड़ों में आइपीएल 2026

आरेंज कैप विजेता	वैभव सूर्यवंशी (776 रन)
पर्पल कैप विजेता	कैगिसो रबाडा (29 विकेट)
सर्वाधिक छक्के	वैभव सूर्यवंशी (72 छक्के)
सर्वाधिक चौके	साई सुदर्शन (75 चौके)

अब तक के विजेता

- चेन्नई सुपरकिंग्स (2010, 2011, 2018, 2021, 2023)
- मुंबई इंडियंस, (2013, 2015, 2017, 2019, 2020)
- केकेआर, (2012, 2014, 2024)
- रायल चैलेंजर्स बेंगलुरु (2025, 2026)
- गुजरात टाइटंस, 2022
- सनराइजर्स हैदराबाद, 2016
- डेक्कन चार्जर्स, 2009
- राजस्थान रायल्स, 2008

आरेंज कैप जीतने वाले सबसे युवा खिलाड़ी बने वैभव सूर्यवंशी पेज>>12

आइपीएल के समापन समारोह में कैलाश खेर ने बिखेरा जलवा पेज>>12

बौद्धिक संपदा

उत्पादों की प्रकृति का प्रश्न

विकास आसावत

पेटेंट संबंधी मामलों के जानकार

आजकल बाजार में ऐसे अनेक उत्पाद मिल जाते हैं जो किसी दूसरी कंपनी के उत्पाद से मेल खाते हैं। ऐसे में बौद्धिक संपदा अधिकारों का हनन हो रहा है जिसे रोकना होगा

पैकेज्ड ड्रिंकिंग वाटर बोटल और मोबाइल फोन से लेकर पेन, लैपटाप, ऑडियो स्पीकर या आटोमोबाइल पर लेबल या नाम के वर्णित न होने पर भी आप दूर से ही उसकी बाहरी डिजाइन, आवरण, विन्यास या सतही पैटर्न देखकर उसके स्रोत या संबंधित निर्माता/ विपणन कंपनी को पहचान लेते हैं। अर्थात किसी भी उत्पाद की पहचान उसके अनुपम डिजाइन और आवरण से आसानी से की जाती है। इसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि इस डिजाइन, आवरण के निर्माण या अवधारणा में आपको क्रिएटिव थिंकिंग के साथ-साथ रिसर्च भी करनी पड़ती है। इस तरह के विशेष उत्पाद को बौद्धिक संपदा के तहत इंडस्ट्रियल डिजाइन या कहें कि डिजाइन अधिकार के तहत संरक्षित किया जाता है।

अब जब हम नवाचार के संरक्षण की बात करते हैं, तो आमतौर पर पेटेंट, कापीराइट और ट्रेडमार्क ही प्रमुखता से सामने आते हैं। आमतौर पर आवेदक को पेटेंट और डिजाइन अधिकार में अंतर करने में असमंजस हो जाता है। जहां पेटेंट अधिकार में हम फंक्शनल इंप्रूवमेंट पर केंद्रित होते हैं, तो उसमें कार्य व कार्यपद्धति महत्वपूर्ण मानदंड होते हैं। वहीं, डिजाइन अधिकार किसी उत्पाद में कार्यपद्धति सामान्य होने पर उसकी बाहरी आकृति और विन्यास विशिष्ट है जिससे उत्पाद देखने में अधिक आकर्षक लगता है, जैसे क्लोथिंग के पैटर्न, फुटवियर के डिजाइन, ज्वेलरी में नवाचार, विशिष्ट आटोमोबाइल पार्ट्स, मोबाइल फोन का आकार, स्टाइलिश फर्नीचर आदि।

डिजाइन पंजीकरण में व्यापक वृद्धि : वर्तमान में लागू भारतीय डिजाइन अधिनियम मई, 2000 को पारित हुआ था। समय के साथ भारत में डिजाइन आवेदनों में भारी वृद्धि देखी गई है। वर्ष 2000-01 में ये 3,207 तक सीमित थे जो वर्ष 2024-25 में बढ़कर 42,992 तक पहुंच गए हैं, जबकि डिजाइन पंजीकरण इसी अवधि में 2,430 से बढ़कर 30,350 हो गए हैं। हाल ही में इस दिशा में एक अप्रत्याशित प्रगति हुई है। वस्तुतः कलकत्ता उच्च न्यायालय ने एक मामले में स्पष्ट किया है कि ग्राफिकल यूजर इंटरफेस (जीयूआइ) डिजाइन अधिनियम, 2000 के अंतर्गत संरक्षण के योग्य हैं। न्यायालय ने माना कि जीयूआइ अपने लेआउट, आइकनोग्राफी, रंग योजनाओं और दृश्य संरचना के माध्यम से एक ऐसा दृश्य प्रभाव उत्पन्न करते हैं जिसे आंखों से परखा जा सकता है, तो वे "डिजाइन" की परिभाषा के तहत आते हैं।

इस निर्णय से भारत प्रभावी रूप से वैश्विक आइपी मानकों के अनुरूप हो जाता है। इस निर्णय को नियमित करने के लिए इसी वर्ष जनवरी में भारत सरकार ने एक 'कांसेप्ट नोट' जारी किया है जो संबंधित डिजाइन कानून में संशोधन को प्रस्तावित करता है। साथ ही, कांसेप्ट नोट के तहत कापीराइट अधिनियम की धारा 15 (2) में संशोधन करके अपंजीकृत, लेकिन पंजीकरण योग्य डिजाइनों को 15 वर्षों तक कापीराइट संरक्षण प्रदान करने की अनुमति देने का प्रस्ताव है जिससे डिजाइन और कापीराइट संरक्षण के बीच परस्पर संबंध से उत्पन्न होने वाली कानूनी अनिश्चितता और विवादों में कमी आए।

वहीं नोट में प्रवर्तन को बेहतर बनाने के लिए, अवधारणा नोट में डिजाइन उल्लंघन के लिए वैधानिक क्षतिपूर्ति लागू करने का सुझाव दिया गया है। जानबूझकर किए गए उल्लंघन के मामलों में न्यायालयों को 50 लाख रुपये तक की क्षतिपूर्ति देने का अधिकार दिया जा सकता है। प्रस्ताव में बार-बार उल्लंघन के मामलों में वैधानिक क्षतिपूर्ति की राशि को भी बढ़ाया गया है, जिससे यह दंडात्मक क्षतिपूर्ति के समान हो जाता है। इसके साथ ही, मामूली या अनजाने में हुई प्रक्रियात्मक चूक के कारण डिजाइन अधिकारों के अपरिवर्तनीय नुकसान को रोकने के लिए भी इस कानून में बदलाव प्रस्तावित है।

दो इलेक्ट्रिक कंपनियों से जुड़े सीलिंग फैन से संबंधित डिजाइन के एक मामले में दिल्ली उच्च न्यायालय ने बचाव पक्ष को दूसरे के पंजीकृत डिजाइन का उपयोग करके निर्माण, विपणन, बिक्री करने से प्रतिबंधित करते हुए कहा कि गैर-जरूरी विशेषताओं में मामूली अंतर भी उस स्थिति में ढाल का काम नहीं कर सकते, जब डिजाइन की आवश्यक विशेषताएं नकल की हुई प्रतीत होती हों। यह इस दिशा में बहुत कुछ विश्लेषित करता है।

उत्पाद का दृश्य स्वरूप यानी उपयोगकर्ता को वह कैसा दिखता है, उसकी सफलता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। मार्केटिंग और प्रोडक्ट डेवलपमेंट ग्रुप के साथ मिलकर काम करने से कंपनियां डिजाइन चक्र के शुरुआती चरण में पंजीकरण योग्य पहलू की पहचान कर सकती हैं, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि इनोवेशन न केवल रचनात्मक हो, बल्कि दीर्घकालिक और कमर्शियल भी हो। किसी भी डिजाइन के वाणिज्यिक उपयोग या सार्वजनिक प्रदर्शन से पहले उसके पंजीकरण के लिए आवेदन दाखिल करना आवश्यक है। डिजाइन पंजीकरण केवल आकार और विन्यास के संरक्षण करने के बारे में दस्तावेज मात्र नहीं है, आज के प्रतिस्पर्धी बाजार में एक सशक्त बिजनेस टूल भी है।

भास्कर एक्सक्लूसिव सोनपुर में देश का तीसरा सबसे बड़ा ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट होगा, टाउनशिप का सर्वे पूरा, जून में कंसल्टेंट बहाली

बिहार की पहली एरोसिटी होगा हरिहरनाथपुर; 11 टाउनशिप में 5 लाख को रोजगार

राकेश रंजन | पटना

बिहार अब विकास की नई रफ्तार पकड़ने को तैयार है। राज्य में पहली बार मेट्रो शहरों की तर्ज पर 11 ग्रीनफील्ड सैटेलाइट टाउनशिप विकसित करने का काम शुरू हो गया है। सर्वे का काम पूरा हो गया है। अगले चरण में कंसल्टेंट बहाली का काम चल रहा है। योजना का सबसे बड़ा आकर्षण सोनपुर का 'हरिहरनाथपुर' होगा, जिसे राज्य की पहली 'एरोसिटी' के रूप में बसाया जाएगा। यहां बनने वाला ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट देश का तीसरा सबसे बड़ा एयरपोर्ट होगा। सारण के सांसद और एविएशन एक्सपर्ट राजीव प्रताप रूडी के अनुसार, यह एयरपोर्ट हैदराबाद के बराबर होगा और अंतरराष्ट्रीय मानकों को पूरा करेगा। बिहार इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के अध्यक्ष रामलाल खेतान का दावा है कि प्रत्येक टाउनशिप में लगभग 50 हजार को रोजगार मिलेगा। इस तरह, सभी 11 टाउनशिप मिलकर राज्य में 5 लाख से अधिक प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार पैदा करेंगे। नगर विकास मंत्री नितीश मिश्रा ने कहा कि सेटेलाइट टाउनशिप का काम तेजी से चल रहा है। कंसल्टेंट बहाल करने के लिए टेंडर निकाला गया है। जून में बहाली प्रक्रिया पूरी हो जाएगी।

किसानों की चांदी... 20 गुना तक बढ़ेंगी कीमतें, एयरोसिटी और स्पोर्ट्स सिटी का अनोखा संगम

बिहार में पहली बार विकास का ऐसा मॉडल तैयार किया गया है जहां एरोसिटी, फिनटेक सिटी और स्पोर्ट्स सिटी को एक साथ जोड़ा गया है। एक्सप्रेसवे, रिंग रोड और रेलवे जंक्शन के आसपास इन शहरों को बसाने से प्राइवेट इन्वेस्टमेंट तेजी से आएगा। आईटी, बैंकिंग और रियल एस्टेट सेक्टर के लिए यह बिहार का 'गोल्डन एरा' साबित होगा। सरकार ने जमीन अधिग्रहण के लिए 'लैंड पूलिंग मॉडल' अपनाया है। इसके तहत किसानों को उनकी विकसित भूमि का 55% हिस्सा वापस कर दिया जाएगा। अनुमान है कि विकास के बाद इन जमीनों की कीमत 10 से 20 गुना तक बढ़ जाएगी। जो किसान योजना में शामिल नहीं होंगे, उन्हें बाजार दर से चार गुना मुआवजा मिलेगा।

पाटलिपुत्र टाउनशिप: 81 हजार एकड़ में नया बिहार... पटना के पास 'पाटलिपुत्र टाउनशिप' सबसे बड़ी योजना है, जो 81,730 एकड़ में फैली होगी। यहां फिनटेक सिटी, आईटी पार्क और अंतरराष्ट्रीय खेलगांव विकसित होगा। वहीं सोनपुर की एरोसिटी के लिए बिहार कैबिनेट ने 1302 करोड़ रुपये मंजूर किए हैं। यह इलाका होटल, लॉजिस्टिक्स और कमर्शियल हब बनेगा। अक्टूबर-नवंबर तक सभी टाउनशिप का खाका तैयार करने का लक्ष्य है।

भास्कर एक्सपर्ट

रामलाल खेतान, अध्यक्ष, बीआईए

इंटरनेशनल हब बनेंगे पटना और सोनपुर

गंगा पर बन रहे नए पुलों से पटना और सोनपुर की दूरी खत्म हो जाएगी। ये दोनों शहर मिलकर एक बड़े अंतरराष्ट्रीय शहर के रूप में विकसित होंगे। यहां फाइव स्टार होटल और कन्वेंशन सेंटर बनेंगे। हरिहरनाथ कॉरिडोर और रिवर फ्रंट डेवलपमेंट से सोनपुर मेले को वैश्विक पर्यटन केंद्र के रूप में पहचान मिलेगी।

Nepal PM sparks row, says his country has encroached upon Indian territory

Sanjeev Satgainya
KATHMANDU

> You might find it strange, but I also learned only recently — after becoming Prime Minister — that it is not just India but Nepal too has encroached upon Indian territories in many places
>
> **BALENDRA SHAH**
> Nepal Prime Minister

Nepal Prime Minister Balendra Shah said on Sunday that his country too had encroached upon Indian territory, in what is considered to be the first such public statement by a head of government of the neighbouring country.

Mr. Shah was responding to a question by a lawmaker in Parliament regarding the Kalapani region, which remains disputed between Nepal and India. "You might find it strange, but I also learned only recently – after becoming Prime Minister – that it is not just India but Nepal too has encroached upon Indian territories in many places," Mr. Shah said, prompting an uproar in Parliament as the Opposition objected to the statement.

Nepal and India have a long-pending boundary dispute over Lipulekh, Limpiyadhura, and Kalapani and the dispute resurfaced recently when India announced the revival of the Kailash Manasarovar Yatra pilgrimage via the Lipulekh route. Nepal then sent diplomatic notes to both India and China. India maintains that the territories are part of Uttarakhand.

Lawmakers from the Nepali Congress and the Nepali Communist Party demanded that the Prime Minister clarify where exactly Nepal has encroached upon Indian territory and sought the removal of his remarks from the record. "The Prime Minister said Nepal has encroached upon Indian territory," Nepali Congress Chief Whip Basana Thapa said. "Where exactly has this happened? The Prime Minister must make the House aware of this. This is a serious and objectionable statement."

CONTINUED ON
» **PAGE 10**
RSP DELEGATION VISIT
» **PAGE 12**

The apex court rings its own chain

The Supreme Court's reliance on *suo motu* cognisance has turned a once 'rare but highly visible' jurisdiction into a recurring instrument shaped by primetime attention and media reports; while it keeps 'ringing' its own chain through televised listings and supervision, the trial courts below it continue doing the work

LETTER & SPIRIT

V. Venkatesan

In 1605, on his accession, the Mughal Emperor Jahangir fastened a chain outside his palace. Any subject denied justice by his administration could pull the chain and reach the emperor directly. The chain was, in conception, a remedy against the bureaucracy. The Indian Supreme Court is now, in its *suo motu* cognisance of individual criminal cases, the bureaucracy itself, ringing its own version of the chain. Each televised listing is the sound of the apex court calling attention to itself.

Media and motive

The latest instance is the court's *suo motu* cognisance of Twisha Sharma's death, registered under the title 'In Re Alleged Institutional Bias and Procedural Discrepancies in the Unnatural Death of a Young Girl at Her Matrimonial Home'. The title prejudges its own inquiry. Institutional bias has not been judicially established at any level. The apex court's own office report, signed by the Assistant Registrar on May 23, records the basis of registration. The case was registered, the document says, 'based on media reports and other attending circumstances'. Two days later, the same bench appealed to the media to refrain from recording statements of witnesses. A court that acts on press reports while admonishing the journalists who filed them is, at the same moment, both consumer and critic of the same source.

The ground on which the apex court arrived was not vacant. A magistrate in Bhopal had remanded the husband, a practising advocate, to seven days of police custody. The Madhya Pradesh High Court had directed a second autopsy by an AIIMS Delhi team. The Bar Council of India had suspended the husband's licence. The State government had proposed transferring the investigation to the Central Bureau of Investigation (CBI) before the apex listing. The institutions whose bias the apex title alleges had been moving against the accused for nearly a fortnight.

Marc Galanter and Vasujith Ram put the central question to this reflex with care. Their study appears in A Qualified Hope (Cambridge University Press, 2019). Why does the response of the higher judiciary to executive or police failure take 'the form of these singular heroic interventions rather than promoting some institutional shake-up, some initiative to empower and equip courts lower in the judicial hierarchy'? Their diagnosis was unsparing. The reflex carries, they wrote, 'an echo of the disdain with which higher courts in India frequently treat the efforts of the lower judiciary'.

Easier path

Suo motu cognisance, in matters of this kind, is the easier of the two paths open to the apex court. The harder path is the slow, unspectacular work of reforming the judiciary it heads. The first requires only the bench's decision to list the matter. The second requires sustained cooperation: with the High Courts on case management and supervision under Article 235 (control over subordinate courts), with State governments on funding trial-court infrastructure, with the executive on judicial appointments, and with the National Judicial Academy on training. The asymmetry between the energies devoted to the two paths is what produces the diagnosis Galanter and Ram named.

Where the easier path is taken, the court chooses persuasion over compulsion. The apex bench has, in *Sahara India Real Estate Corporation v. SEBI* (2012), a five-judge Constitution Bench authority on media trial. Sahara permits a court to issue a postponement order against media publication. The test is a real and substantial risk of prejudice to the administration of justice. The order is available only where no less restrictive means will work. The doctrine is settled. In the Twisha matter, the bench had every occasion to invoke it. It chose instead to request the media not to record statements of potential witnesses. A request from the apex court carries moral weight. But it is not the legal instrument it has at hand for this very problem.

The post-2019 record is unkind to the pro-*suo-motu* case. In the R.G. Kar matter, the Supreme Court registered cognisance on August 18, 2024. Sanjay Roy had been arrested by the Kolkata Police eight days earlier. The Calcutta High Court had handed the probe to the CBI on August 13, 2024. The Sealdah trial court convicted Roy in January 2025 and sentenced him to life imprisonment. The trial judge did the work. Apex monitoring of CBI status reports did not.

Hathras is closer to the Bhopal facts and more instructive. The Lucknow bench of the Allahabad High Court registered the case *suo motu* in October 2020. The Supreme Court, after entertaining transfer petitions, handed monitoring back to the High Court within weeks. That earlier bench saw the architectural point: the High Court was already in motion, and the apex role was supervisory. In July 2024, following the Hathras Satsang stampede that claimed 121 lives, the court declined a PIL. The bench said that the High Court was equipped to deal with the case. The same principle applies in Bhopal too.

Scarce attention

Lakhimpur Kheri sharpens the matter. The apex court took cognisance in October 2021 and, in April 2022, set aside the High Court's bail order for the main accused, Ashish Mishra. It then eased him back into liberty. Interim bail came in 2023. Regular bail followed in 2024. As of early 2026, the trial court had examined only 44 of 131 witnesses. In Manipur, the *suo motu* case over the viral video from July 2023 has yet to produce a conviction. Apex supervision has not been the route to faster justice.

A second observation runs alongside. In 2019, Galanter and Ram called *suo motu* 'rare but highly visible'. The first half of that description has lapsed. What was once a residual jurisdiction is now a recurring instrument. A trigger sequence has begun to repeat. Sustained primetime attention is followed by cognisance. The Solicitor General has now confirmed the sequence in open court. Appearing for the Union in the Twisha matter, he told the bench that 'it is also because of this media intervention that a lot of progress has happened'.

The numbers since the chapter, authored by Galanter and Ram, went to press confirm the rule. The Supreme Court Observer, working from the apex court's own Case Status records, counts 35 *suo motu* matters in the five years from 2020 to 2024.

The preceding fifteen years had seen only 31 in total. The annual figures, excluding contempt, were 10 in 2020, eight in 2021, one in 2022, four in 2023, and 12 in 2024. The trend continues. In 2025, the court's numbering reached 10 civil *suo motu* writs and three criminal matters. Nine of the 10 civil matters are publicly listed. By May 25 this year, the count already stood at four civil and four criminal matters. Both totals exclude *suo motu* transfer and contempt, which exercise distinct constitutional powers. The criminal count, in particular, has risen sharply. Four months and three weeks have already exceeded the criminal count for all of 2025.

Judicial attention is a scarce resource. The National Crime Records Bureau recorded 6,450 dowry deaths in 2022, with convictions in only 11 to 17 per cent of cases. The court has the capacity to list one. The criterion of selection is, on the present record, temporal rather than legal. Galanter and Ram closed their chapter with a question. They asked whether *suo motu* was 'an instance of effective use of the scarce resource of judicial attention'. The seven years since they wrote have not produced an easier answer.

None of this is to deny the seriousness of the Twisha Sharma matter. The accused's mother is a retired judge. The husband is a lawyer. The family of the deceased has reason to fear local proximity. The constitutional response to that fear is independent investigation under judicial supervision, conducted promptly. The court, however, disposed of the matter on the first day after taking note of the "narrative" in the media that a fair investigation was being denied on account of the involvement of the judiciary.

The chain Jahangir hung was a remedy against an unaccountable bureaucracy. The apex court is now that bureaucracy. Each televised listing is the sound it makes to draw attention to a failure it has the power, and the constitutional duty, to repair. Until the harder of its two paths is walked with the energy now devoted to the easier one, the chain will keep ringing. The trial courts below it will keep doing the work.

(V. Venkatesan is a journalist and legal researcher.)

GETTY IMAGES

THE GIST

The ground on which the apex court arrived was not vacant, with the magistrate, the High Court, the Bar Council of India and the State government already acting in the Twisha Sharma case.

The harder path before the apex court is the slow, unspectacular work of reforming the judiciary through better case management, trial-court infrastructure, appointments and training.

Judicial attention is a scarce resource, but sustained primetime attention is increasingly followed by cognisance, raising questions about the use of that attention.